रहा है क्या किसानों को उसका मुआवजा देने की कृपा करेंगे ? और दीषी अफ़सरों ने जो बाजरा नहीं खरीदा उनके खिलाफ आप ऐक्शन लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है कि एक तो आप कहते हो कि काम नहीं करते, और दूसरी तरफ उनकी सिफारिश भी करते हो।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह भी काम नहीं करते हैं और आप मंत्री जी की सिफारिश करते हो, तो बराबर हो गया।

अध्यक्ष महोदय : यह जवाब का प्रश्न नहीं है, लेकिन आप मंत्री जी खरीद का बन्दोबस्त देख लेंगे।

श्री भीखा भाई : मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है वह यह है कि इन्होंने क्लास 3 और 4 को अंतिरिम सहायता दे दी है। दरअसल में मुख्य मांग अंतरिम राहत की नहीं हैं, बल्कि उनकी मुख्य मांग यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐप्लाईज के आधार पर जो वेज रिवीजन होना चाहिये वह कब करने जा रहे हैं ?

दूसरे यह कि इन्होंने जो बताया कि यह प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर का है इसमें दो तिहाई लोग इंडस्ट्रियल इंडैक्स से गाइड होते हैं और एक तिहाई को सेन्ट्रल गवर्नमेंट पैटर्न पर दिय जाता है, तो उसका कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं आया।...

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो भीखा भाई जी एक ही हो सकता है, इतने सारे नहीं। मंत्री जी आप बता दीजिये।

श्री भीखा भाई : रिवीजन कब तक करेंगे?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा एफ० सी० आई० कर्मचारियों की वेज और डी० ए० पैटर्न सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के आधार पर है लगभग। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐम्प्लाईज को जब जब डी० ए० इंस्टालमेंट मिला वैसा ही इस पर लागू हो जाता था। 1971 से कोई रिवीजन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐमप्लाईज का नहीं हुआ। एफ० सी० आई० ने बार-बार कुछ सालों से मांग की उनको इंडस्ट्रियल डी० ए० में लाया जाय। हमने उनको अंतरिम राहत दी है और यह कहा है कि इंडस्ट्रियल डी० ए० फौरमूला के अन्तर्गत आने के लिए जो आवश्यकतायें हैं वह पूरी हों, जैसे (1) ऐसोसिएशन और यूनियन के सदस्य मैजारिटी से इस बात को कहें, (2) जो वर्किंग आवर टोटल और वर्किंग आवर के भिन्न भिन्न टाईपिंग हैं यह मान लें। ज्यों ही इन बातों पर निर्णय हो जायगा क्लास 1 और क्लास 2 द्वारा हम इनकी वेज पर विचार कर सकते हैं।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में पानी और सीवर की व्यवस्था

167. **श्री सज्जन कुमार†** :
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में पानी और सीवर की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और दिल्ली में इन पुनर्वास कालोनियों के नाम क्या हैं, जिनमें इस योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान पानी और सीवर की लाइनें डालने का कार्य शुरू हो जायेगा और यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार ने इस काम को शीघ्र करने के लिए कोई निर्देष जारी किये हैं और यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details are contained in the statement which is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) Yes, Sir.

(b) The scheme sanctioned by the Govt. envisages provision of the following additional facilities in the resettlement colonies:—

1. water supply lines for individual connections;

2. Sewerage;

3. Improvement of storm water drains and culverts;

4. Improvement of roads and paths;

5. Peripheral services; and

6. Over-head tanks and under-ground tanks.

The DDA who are implementing the scheme have intimated that during 1983-84, work on the scheme for providing water supply and sewerage lines is being commenced in the following colonies after getting the requisite approvals form the MCD:—

1. Madipur.
2. Khyala
3. Hastsal
4. Pankha Road
5. Seelampur
6. Nand Nagri
7. Gokalpuri
8. Old Seemapuri
9. New Seemapuri

(c) The DDA has stated that the work is being expedited as per the policy of the Government.

श्री सज्जन कुमार : अध्यक्ष जी, दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियां हटा कर करीब 12 लाख लोगों को दिल्ली की पुनर्वासित कालोनियों में बसाया गया, और मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में नहीं, शायद दुनियां के किसी देश में एक साथ 12 लाख लोगों को हटाकर शायद ही कहीं पर रीसैटिल किया गया होगा, वहां बहुत सी नागरिक सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन पहली बार प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जो इनको पीने का पानी देने और सीवर डालने की योजना शुरू की है। दिल्ली के सभी क्षेत्रों में उसका स्वागत किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन कालोनीज़ के नाम दिए गए हैं, क्या उनके अलावा और पुनर्वास कालोनीज़ में भी सरकार काम शुरू करने जा रही है, यदि हां, तो वह काम कब तक शुरू किया जाएगा और वह कब तक पूरा किया जाएगा।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इतने विस्तृत प्रोग्राम हो हाथ में लेकर डी डी ए और दिल्ली प्रशासन ने इतने थोड़े समय में जिस तरह काम किया है, वह बहुत सराहनी है। इतने थोड़े समय में वाटर सप्लाई लाइन्ज़ 46 किलोमीटर, रोड एंड पाथ इम्प्रुवमेंट 110 किलोमीटर, स्टार्म वाटर ड्रेन्ज़ एंड कल्वर्ट्स इम्प्रुवमेंट 69 किलोमीटर और सीवर लाइन्ज़ 10 किलोमीटर का काम किया गया है और चार ओवरहैड एंड अंडरग्राउंड टैंक बनाए गए हैं। 20-नुकाती प्रोग्राम का जितना अच्छा इम्प्रूमेंटेशन दिल्ली में, और खासकर पुनर्वास कालोनीज़ में, हुआ है, इसमें संदेह नहीं है कि यह एक आल-टाइम रिकार्ड है। जिन कालोनीज़ के बारे में स्टेटमेंट में विवरण किया गया है, उनके अतिरिक्त डी डी ए की तरफ़ से सरकार के पास त्रिलोकपुरी कम्पलेक्स, रघुवीरनगर, नारायना, पांडवनगर, चौखंडी, ज्वालापुर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नांगलोई फ़ेज़ 1, 2, 3, जहांगीरपुरी, शकूरपुर, बज़ीरपुर, दक्षिणपुरी, मदनगीर, सनलाइट कालोनी ओर मोतीबाग के बारे में सुझाव और योजनाएं पहुंच चुकी हैं। प्राधिकरण की तरफ़ से यह भी मांग की गई है कि इसके लिए अधिक धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी। माननीय सदस्य ने जिन सार्वजनिक सुविधाओं का उल्लेख किया है, उनका

प्रावधान इन कालोनीज में दिया जाएगा। सरकार इस बारे में विचार कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि हम दिल्ली में अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पीने का पानी, अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग और सीवरेज की सर्विसिज़ दे सकें। डी डी ए की तरफ़ से इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने नागरिक सुविधाएं देने के सम्बन्ध में 9 कालोनीज के अलावा और कई कालोनीज का नाम लिया है। मंत्री महोदय ने प्रश्न (ग) के जवाब में कहा है कि सरकारी नीति के अनुसार कार्य शीघ्र ही किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी नीति क्या है और 9 कालोनीज के अलावा जिन और कालोनीज का नाम मंत्री महोदय ने लिया है, डी डी ए ने उनके सम्बन्ध में जो योजना मंत्रालय के पास भेजी है, उस पर कब तक विचार कर लिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि दिल्ली में अब और कितनी ऐसी कालोनीज शेष रह गई हैं, जिनमें यह कार्य प्रारम्भ करने की योजना है। दिल्ली के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों को प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय बड़ी जागरूकता प्रदर्शित कर के दिल्ली में नई दिशा और नई रोशनी और झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब मजदूरों को पानी और बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी कार्य हो रहा है, मंत्री महोदय या उनके उच्चाधिकारियों ने उसका निरीक्षण किया है, ताकि कार्य में कोई गड़बड़ी न हो और कार्य तेजी से हो, जल्दी हो।

MR. SPEAKER : Shri Bhiku Ram Jain.

PROF. N. G. RANGA : What about the reply ?

MR. SPEAKER : He is satisfied.

PROF. N.G. RANGA : How many colonies, how many of them are re-settlement colonies and by what time ?

MR. SPEAKER : He has already enumerated them, that he is going to start work.

PROF. N. G. RANGA : The number he has not given.

श्री भीखू राम जैन : मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह लिखा है—Schemes sanctioned by the Government envisages provision of the following additional facilities in the resettlement colonies. मैं इस बात की और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में जमीन की कीमतें बाकई बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर 1 रुपये का 50 हजार नहीं है तो ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय : अगर दिल्ली को इस तरह बड़ाते जाओगे तो और क्या होगा ?

श्री भीखू राम जैन : मैं उसकी जिम्मेदारी इस बात पर लगाना चाहता हूं कि दिल्ली में जो मकान बनाने की इजाजत दी जा रही है, कहीं दो मंजिल कहीं 3 मंजिल, बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर मल्टीस्टोरीड बिल्डिगें बनाने की इजाजत दी जा रही है, डी० डी० ए० ने खुद जो फ्लोर एरिया रेशियो पहले 150 था उसे ऊंची बिल्डिग बना कर 400 किया है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सीवर डाले जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, पीने का पानी का इन्तजाम किया जा रहा है, क्या वह इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए जो ऊंची बिल्डिगें बनाई जा रही हैं, उनमें इन सारी बातों का पूरा इन्तजाम किया जा रहा है या नहीं? कहीं दो चार साल के बाद यह कहने का मौका तो नहीं आयेगा कि सीवर की लाइन छोटी है पानी की लाइन छोटी है, सड़कें छोटी हैं इसलिये और ऊंची बिल्डिग बनाने की जरूरत नहीं है ? अगर इस प्रकार का विचार है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दिल्ली में मल्टी स्टोरी बिल्डिगें क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा बनाई जायें ताकि दिल्ली में जो जमीन की कीमतों की समस्या है, वह हल हो सके ?

SHRI BUTA SINGH: The hon. Member would agree with me that for some time past now we have changed the whole concept. We have now decided that we will have high density houses, where more people could be accommodated within the same place. This has resulted really in a reduction in land prices in Delhi, which should be complimented.

I agree with the hon. Member that the shortage of land in Delhi has become very very acute. I propose to hold a meeting with the hon. Members especially those from Delhi to have their views and co-operation on the future development of Delhi. As I mentioned and a little while ago by Shri K C Pande, the 20-Point programme of the Government would serve the people of Delhi. We would welcome suggestions from all Members of Parliament especially from Delhi, and we will seek their co-operation to see that the development of Delhi takes place, according to the prescribed norms and rules.

Meeting of State Food and Civil Supplies Ministers

*168. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of State Ministers of Civil Supplies was held recently with the Central Minister in New Delhi in November, 1983;

(b) if so, whether the working of the fair price shops in the States and also the items catered by them was considered at the meeting and if so, brief details thereof;

(c) whether the meeting considered the desirability of expanding such fair price shops in the difficult and rural areas with more items so that the benefit may reach to the population who are cut off and are being exploited by petty traders; and

(d) the decision taken in this regard, if any ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) to (d) Yes, Sir. The fourth Meeting of the Advisory Council on Public Distribution, of which the Civil Supplies Ministers of States/Union Territories are its members, was held on the 7th of November, 1983. At this meeting the expansion of the public Distribution System through opening of more fair price shops, including mobile shops, in the far flung areas and widening the 'scope of coverage of commodities distributed through the Public Distribution System, *inter alia* was reviewed. Keeping in view the important role played by the Public Distribution System in the supply of essential commodities of mass consumption to people at reasonable prices, the general consensus in the Meeting was that the base of the Public Distribution System should be strengthened through planned expansion, proper management and its accessibility to remote and sparsely populated areas. The State Governments and Union Administrations should make efforts to open more fair price shops to achieve the norm of 2000 units per fair price shop. For making fair price shops viable, State Governments and Union Territory Administrations, may include in addition to the essential commodities, for which supplies are made by the Central Government, as many items as could be possible to widen the commodity coverage.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: In part 'C' of my question I have asked whether the meeting considered the desirability of expanding such fair price shops in the difficult and rural areas. In reply to that, the Minister has generalised the problem and not given any specific plan. If any plan has been discussed in the meeting, let the Minister indicate that and then the answer will be complete.

As you are aware, the public distribution system needs to be strengthened and more shops are to be opened in rural and difficult areas. What steps are being taken by the Central Government of making these fair price shops viable ? If viability is not coming, then how will the Central Government ensure more items to the fair price shops and see that they work properly in rural and urban areas ? How will the Government arrange to distribute essential items to the people in general in those areas where there are no fair price shops ?